छोटे जिलों में माल बेचने वाली 3500 इकाइयां हो गईं ग्लोबल

निर्यात प्रोत्साहन योजना का दिखा लाभ, विशिष्ट पहचान के लिए 22 उत्पादों से बढ़कर 46 को मिला जीआई टैग

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। सूक्ष्म और छोटे उद्यमी जो अपने उत्पाद जिले के बाजारों में ठीक से नहीं पहुंचा पाते थे, वे आज करीब 40 देशों में माल बेच रहे हैं। छोटे उद्यमियों को ये आसमान प्रदेश सरकार की निर्यात प्रोत्साहन योजना से मिला है। निर्यात प्रोत्साहन और सुविधा के लिए करीब 3000 सूक्ष्म और छोटी इकाइयों ने पंजीकरण कराया है। करीब 3500 इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय मेलों में हिस्सा लेने के लिए 28 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं, विशिष्ट पहचान के लिए 22 से बढ़कर 46 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है।

निर्यात प्रोत्साहन व्यूरो उत्तर प्रदेश के मुताबिक प्रदेश से लगातार निर्यात बढ़ रहा है। वर्ष 2017-18 में 89 हजार करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 1.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2019-20 में यह 1.20 लाख करोड़ और 2020-21 में 1.21 लाख करोड़ हो गया। वर्ष 21-22 में यह बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 22-23 में बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

निर्यातकों के काम सरकारी दफ्तरों में न अटके और उनके काम पूरे सम्मान के साथ वरीयता में किए जाएं, इसके लिए गोल्ड व सिल्वर कार्ड स्कीम बनाई गई है। एक वर्ष में 50 लाख रुपये से ज्यादा का टर्नओवर करने वाले निर्यातकों को गोल्ड व 20 लाख का टर्नओवर करने वाले निर्यातकों को सिल्वर कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्डधारकों को किसी भी विभाग में बिना पास के बेरोकटोक आने की सुविधा दी गई है। अब ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर गोल्ड कार्ड लेने की प्रतिस्पर्धा का नतीजा ये है कि 738 इकाइयों के पास गोल्ड कार्ड है। 62 इकाइयों के पास सिल्वर कार्ड है।

जहाज से माल भेजने पर सब्सिडी का असर निर्यात पर

ग्लोबल प्लेटफार्म पर उत्पाद बेचने की दो बड़ी चुनौती होती हैं गुणवत्ता और कीमत। गुणवत्ता के मोर्चे पर यहां के उद्यमी जीत जाते थे, लेकिन कीमत की लड़ाई में कमजोर पड़ जाते थे। इसमें भाड़ा सबसे बड़ी बाधा थी। इसे अनुदान योजना ने दूर कर दिया। गेटवे पोर्ट तक मालभाड़े के लिए पहले 20 फीट कंटेनर पर छह हजार रुपये और 40 फीट पर 12 हजार रुपये अनुदान था। कोरोना संकट के बाद जहाज कंपनियों ने इसे दोगुना कर दिया। इसके मद्देनजर उद्यमियों को 10 हजार और 20 हजार रुपये प्रति कंटेनर अनुदान दिया गया। इस मद में 5800 निर्यातकों को करीब 72 करोड़ रुपये दिए गए।

अनुदान योजनाओं से पांच साल में दोगुना हुआ निर्यात

सरकार की अनुदान योजनाओं का ही परिणाम है कि निर्यात लगातार बढ़ रहा है। कोरोना काल के बावजूद पांच साल में दोगुना निर्यात हो गया। छोटे उद्यमियों और ओडीओपी योजना का इसमें अहम योगदान है।

– नंद गोपाल गुप्ता नंदी, औद्योगिक विकास व निर्यात प्रोत्साहन मंत्री।